घोषणावीर खट्टर के 1000 रेन वाटर हार्वेस्टर कहां लुप्त हो गये ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) इस शहर के साथ-साथ पूरे राज्य में घोषणाओं की बरसात करते घोषणावीर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने हजार करोड़ के तोहफों की झड़ी राज्य भर में लगा दी इसका पूरा हिसाब तो खुद खट्टर के पास भी नहीं है। इन घोषणाओं को पूरा करने लायक धन उनके राजकोष में है भी या नहीं, खट्टर को यह सब जानने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि घोषणाओं पर तो कुछ खास खर्च होता नहीं है सिवाय भीड़ एकत्र करने के। कहीं-कहीं शिलान्यास पर जरूर छुट-मुट खर्चा होता है बाकी काम करना तो इनकी किताब में लिखा ही नहीं। न मोदी ने 15 लाख दिये, न गडकरी का मंझावली यमुना पुल बना। झूठ बोलने पर इस देश में कोई सजा है नहीं।

करीब छह माह पूर्व इसी शहर में आये खट्टर ने यहां 1000 रेन वाटर हार्वेस्टर लगाने का आदेश नगर निगम अधिकारियों को दिया था। यहां के गिरते भूजल स्तर को और अधिक गिरने से बचाने के लिये इन हार्वेस्टरों की आवश्यकता इस शहर को है। सीएम की थोथी घोषणाओं व फर्जी आदेशों को समझते हुए शहर के

कुछ प्रबुद्ध लोगों ने भुवनेश धींगड़ा फाऊंडेशन के माध्यम से मेट्रो सिनेमा रोड पर एक रेन वाटर हार्वेस्टर लगाने का काम शुरु किया था। इसकी बाकायदा लिखित अनुमति नगर निगम से ले ली गयी थी। उसके बावजूद निगम ने अधूरे काम को बीच में ही रोक दिया जिस पर लाखों रुपया खर्च हो चुका था। यह रुकावट विधायक सीमा त्रिखा द्वारा केवल इसलिये पैदा की गयी थी कि इसके निर्माण से उनके संभावित प्रतिद्वंदी योगेश ढींगड़ा की लोकप्रियता बढ़ सकती थी। ढींगड़ा इसी क्षेत्र से एक स्वच्छ छवि वाले पार्षद रह चुके हैं।

चलो, सीमा ने अपनी चाल चलकर ढींगड़ा का सर्वजन हिताय प्रोजेक्ट तो रोक दिया, परन्तु खट्टर के उस आदेश का पालन तो कराया होता जिसके द्वारा 1000 रेन वाटर हार्वेस्टर यहां लगने वाले थे। क्या विधायक सीमा की राजनीतिक शक्ति केवल जनहिताय कामों को रोकने भर की ही है या उन्हें कराने की भी है? इतना ही नहीं अपने क्षेत्र के तमाम गली मौहल्लों में भी विधायक महोदया की दादागिरी इसी तरह चलती है। जहां इनके विरोधी रहते हैं वहां नगर निगम को कोई काम नहीं करने दिया जाता। निगम केवल वहीं सीवर, सड़क के लाइटों का एवं रख रखाव करती है जहां के लिए विधायक कहती हैं और विधायक केवल उन्हीं के लिये कहती हैं जो इनकी चापलूसी करें। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी बताया कि यदि वे कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का झंडा लगा लें तो उनके यहां वह तुरन्त तोड़फोड़ करा देगी। ऐसी दहशत है सीमा की अपने क्षेत्र में।

विधायक सीमा त्रिखा की बड़खल झील कब भरेगी ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) बड़खल विधानसभा से निर्वाचित विधायक सीमा त्रिखा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनेकों वायदों के साथ-साथ बरसों पुरानी झील को पानी से लबालब भर कर पुर्नजीवित करने का वायदा भी किया था। उनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने को आया है परन्तु बड़खल झील की हालत जस की तस तो है ही, उसमें पानी भरे जाने के कोई आसार भी नजर नहीं आते। लोकसभा के साथ ही यदि हरियाणा विधानसभ के चुनाव भी हो गये तो सीमा का कार्यकाल मात्र ढाई माह बचता है और यदि अपने निर्धारित समय अक्टूबर में होते हैं तो 6-7 माह बचते हैं।

देखने वाली बात यह है कि जो काम उनसे साढ़े चार साल में नहीं हो पाया उसे वह इन चंद महीनों में कैसे कर पायेंगी? बिल्कुल भी नहीं। हां बातों के पकौड़े जरूर तलती रहेंगी। जैसे एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाकर सैक्टर 21 के सड़े पानी को साफकरके झील में भरा जायेगा। इसके लिये करोड़ों रुपए का एसटीपी लगेगा। इससे निकले शोधित पानी को झील तक पहुंचाने के लिये करोड़ों रुपये की लागत से पाइप लाइन बिछाई जायेगी। लेकिन जबानी जमा-खर्च के अलावा धरातल पर अभी तक कुछ भी बनता नजर नहीं आया।

इसमें भी गंभीर बात तो यह है कि शहर में पहले से चल रहे एसटीपी जो जल शोधन कर रहे हैं, इसका नमूना देखा जा सकता है तिगांव रोड पर गांव मिर्जापुर के निकट स्थित एसटीपी का हाल देखकर। इसके तथाकथित शोधित जल ने गांव वालों का जीना दूभर कर रखा हैं गांव की कई एकड़ जमीन में पड़ा यह पानी इस कदर सड़ रहा है कि तिगांव रोड व बाईपास तक इनकी दुर्गन्ध को महसूस किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि एसटीपी से जल संशोधन होता ही नहीं है, खूब होता हे, परन्तु यह काम नगर निमग के हरामखोर व रिश्वतखोर अफसरों के बस का तो कतई नहीं।

यहां अहम सवाल यह भी पैदा होता है कि पहले इस झील में पानी कहां से और कैसे आता था, विदित है कि पहाड़ियों में बरखा का पानी बहकर इतनी मात्रा में आता था कि झील तो लबालब भरती ही थी फालतू पानी इसके गेट खोलकर बहा दिया जाता था। वही बरसाती पानी अब भी इन पहाड़ियों में बरसता है, जरूरत केवल उसके बहाव को झील की ओर करने की है जो अवैध खनन के चलते अवरुद्ध हो गया है परन्तु इस काम को करने से उतनी लूट कमाई संभव नहीं जितनी एसटीपी लगाने व पाइप लाइन बिछाने से हो सकती है। लेकिन इतना पैसा न कभी आयेगा और न यह प्रोजेक्ट कभी पूरा होना तो दूर शुरु होना ही मुश्किल है।

चलों झील न भरी तो न सही बाकी कौन से काम कर दिये मैडम जी ने? उनके क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा सरकारी बीके अस्पताल व उसकी डिस्पेंसरियों की हालत बद से बदत्तर होती जा रही है। सरकारी स्कूल भयंकर दुर्दशा का शिकार हैं। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला पड़ा है। पुलिस के उच्चाधिकारियों के सीधे संरक्षण में शराब व जुए सट्टे के ऑफिस खुले आम धंधा कर रहे हैं। हां, सीमा त्रिखा इन माफियाओं के समर्थन में जरूर देखी जा सकती है। इसके साथ-साथ अवैध कब्जे व निर्माण करने वालों को भी विधायक महोदया पूरा सहयोग करती हैं। नगर निगम द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी सड़क व नाली पर नारियल फोड़ने से वे कभी नहीं चूकती।

कनवर्जन पत्रों के बदले वोट भी चाहिये और नोट भी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 6 मार्च को स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर तथा विधायक सीमा त्रिखा ने 20 दुकानदारों को वे कनवर्जन प्रमाणपत्र दिये जिनसे, घरों में चलने वाली उनकी अवैध दुकानें वैध हो जायेंगी। पूरी ड्रामेबाज़ी के साथ म्यूनिसिपल सभागार में ये प्रमाणपत्र ऐसे बांटे गये जैसे इन नेताओं ने दुकानदारों पर बड़ा भारी एहसान कर दिया हो और उसके बदले में उन्हें चुनाव में वोट दें।

विदित है कि उक्त 20 दुकानदारों के अतिरिक्त करीब 680 ऐसे और दुकानदार भी हैं जिन्होंने इन्हीं के साथ 7000/-रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से कनवर्जन के नाम पर निगम में पैसा जमा करा रखा है। इन सब ने यह पैसा करीब 7-8 वर्ष पूर्व नगर निगम में जमा कराया था। तब से लेकर अब तक ये तमाम दुकानदार नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। सम्बन्धित बाबू एवं अफ़सर पैसे मांगते हैं और नेता सुनते नहीं। हां अब चुनाव सिर पर आये तो नेताओं को इन दुकानदारों की याद आ गयी।

बांटे गये प्रमाणपत्रों के लिये पूरी राजनीतिक ड्रामेबाज़ी करते हुए उक्त दोनों नेताओं (सांसद व विधायक) के अलावा मेयर तथा निगमायुक्त भी मौजूद थीं। जबकि यह प्रमाणपत्र किसी बाबू द्वारा अथवा डाक द्वारा भी सम्बन्धित लोग़ों को भेजे जा सकते थे। परन्तु हर काम को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने वाले हर काम को ऐसे करते हैं मानें वे जनता पर बड़ा अहसान कर रहे हों और इस अहसान के बदले दुकानदार उनको ही वोट दे कर पुन: अपने सिर पर बैठायें।

उक्त 700 दुकानदारों द्वारा जो पैसा जमा कराया गया था उसे कनवर्जन चार्ज कहा गया है यानी रिहायशी स्थल को व्यापारिक स्थल में परिवर्तित करने का चार्ज। वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा तय किये गये ऊंचे कनवर्जन चार्ज की जगह नगर निगम के सदन ने 1000 से 1500 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से लगाने का प्रस्ताव पारित किया था जिसे सरकार ने बढा कर छ: से सात हज़ार कर दिया था। दुकानदारों ने इसे भी स्वीकार कर लिया और पैसे भर दिये थे।। परन्तु इसके बावजूद इन लोग़ों को सात-आठ साल तक प्रमाणपत्र के लिये घुमाया गया।

इसके बाद कुछ अन्य सड़कों के लिये परिवर्तन की स्वीकृति सरकार की ओर से दी गयी। लेकिन इस बार कनवर्जन चार्ज 15000 रुपये तक कर दिया गया। सरकार द्वारा की गयी इस अनाप-शनाप वृद्धि का दुकानदार विरोध कर रहे हैं। भाजपा की खट्टर सरकार के पास कोई तर्क नहीं है कि यह कनवर्जन चार्ज इतना कैसे और क्यों बढा दिया गया?

वास्तव में रिहायशी स्थलों के मुकाबले व्यापारिक स्थलों के दाम इस लिये थोड़े ऊंचे रखे जाते हैं कि वहां पार्किंग, जनसुविधाओं आदि की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। परन्तु यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। यहां तो सारा खेल किसी न किसी बहाने जनता से पैसा लूटने का यह एक जरिया मात्र है। जिन दुकानदारों ने कनवर्जन के नाम पर नगर निगम के खजाने में करोड़ों रुपया जमा करा दिया, उनके क्षेत्र यानी उनकी सड़कों पर नगर निगम ने किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं बढाई है। केवल पैसा हड़प कर निगम ने कुछ समय के लिये अपनी कंगाली जरूर दूर कर ली है।

जो नगर निगम अवैध दुकानों को सील कर सकता है, तोड़ सकता है, कनवर्जन चार्ज वसूल कर सकता है तो क्या वह दुकानदारों द्वारा कब्जाई गयी फुटपाथ खाली नहीं करा सकता? क्या दुकानों के सामने 10-10 फ़ीट तक सड़क घेर कर रखे सामान को नहीं हटवा सकता? बाज़ारों में आने वाली आम जनता को निगम द्वारा डकारे गये कनवर्जन चार्ज से कोई लाभ नहीं, उन्हें तो लाभ तब हो सकता है जब चलने को फुटपाथ व सड़कों पर रखे सामान को हटाया जाये।

नगर निगम ने बड़ी तत्परता एवं सख्ती दिखाते हुए सेक्टर 9-10 की विभाजक सड़क की दुकानों को बंद करा दिया, अच्छा किया। परन्तु यही अच्छा सेक्टर 7-10 की सड़क पर क्यों नहीं किया? क्या वहां से निगमायुक्त का लेन-देन अच्छा हो गया या केवल भाजपा विधायक मूलचंद का इशारा मात्र था? वैसे, करीब 15 वर्ष पूर्व इस सड़क पर भी नगर निगम ने दुकानें बंद कराने की पूरी कार्यवाही की थी, कांटेदार तार के अलावा दीवारें तक खड़ी करा दी थीं लेकिन अब लेन-देन के बाद सब मामला सुलट गया है।

क्या एक राजनीतिक दल अपने हितों के लिए कर रहा है हमारी सेना का इस्तेमाल ?

अपूर्वानंद

भारतीय प्रधानमंत्री ने 'पायलट प्रोजेक्ट' वाला बयान देकर साबित किया कि घृणा से गढ़े गए स्वभाव की तुच्छता किसी भी क्षण की गंभीरता और किसी पद की गरिमा से बाधित नहीं होती.

पतन की कोई सीमा नहीं हो सकती, यह कल भारत के प्रधानमंत्री के बयान से एक बार फिर जाहिर हुआ है.

जब विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देते वक्त उन्होंने यह कहा कि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और असली काम अब शुरू होगा क्योंकि जो हुआ वह अभ्यास था, तब किसी भी संवेदनशील इंसान के मन में जो पहला भाव उठा वह घिन का है.

यह वक्तव्य तब दिया जा रहा था जब भारत का एक लड़ाकू पायलट पाकिस्तान की कैद में था और उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का उसे रिहा करने का ऐलान आया था. इस घोषणा से पूरे देश ने राहत की सांस ली.

पाकिस्तान और दुनिया में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस कदम की सराहना होने लगी थी. भारतीय प्रधानमंत्री ने यह बयान देकर साबित किया कि घृणा से गढ़े गए स्वभाव की तुच्छता किसी भी क्षण की गंभीरता और किसी पद की गरिमा से बाधित नहीं होती.

भटनागर पुरस्कार के अवसर का इस्तेमाल एक फूहड़ व्यंजना के माध्यम से जंगबाजी को उकसावा देने के लिए किया जाए, यह अपने आप में वितृष्णा पैदा करता है. उसके आगे, यह प्रधानमंत्री की क्रूर बेहिसी का भी सबूत है क्योंकि पायलट शब्द उस समय सिर्फ अभिनन्दन से ही जुड़ा हुआ था.

भारत की युद्ध में रणनीतिक हार के मौके को जीत में बदलने की यह दयनीय कोशिश है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके दल का साथ भारत का लगभग सारा मीडिया दे रहा है.

इमरान खान के इस कदम को पाकिस्तान को पीछे हटने को बाध्य कर देने की भारतीय बहादुरी बताया जा रहा है जो कि यह कतई नहीं है.

पिछले दो दिनों में भारतीय सरकारी नेतृत्व सोया हुआ पाया गया. बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई की पहली खबर भी दुनिया को पाकिस्तान ने दी. उसी तरह भारतीय लड़ाकू जहाज को गिराए जाने और एक पायलट को पकड़ लेने की खबर भी भारत की जनता को पाकिस्तान से मिली.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब देश के लोगों की सांसें अटकी हुई थीं, इस देश के प्रधानमंत्री अलग-अलग जगह भारत के करदाता के पैसे पर अपने दल का चुनावी प्रचार कर रहे थे.

इसे सबने नोट किया है कि 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के पाकिस्तान की सीमा पार करने की घटना के बाद इस सरकार ने देश को सीधे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा.

यह खबर पहले से ही तत्पर मीडिया के द्वारा उड़ाई गई कि वायुसेना की बमबारी में तीन सौ दहशतगर्द मारे गए हैं. अल जखीरा और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संचार माध्यमों ने ठीक बालाकोट जाकर जो रिपोर्ट की, उसमें किसी के मारे जाने का कोई सबूत या किसी बड़े दहशतगर्द ठिकाने के तबाह होने का कोई चिह्न नहीं मिला.

पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने एक मरे हुए कौवे को दिखलाकर कहा कि एक मौत जरूर हुई है! फिर भारत की जनता को क्यों धोखे में रखा जा रहा रहा था?

क्यों भारतीय वायुसेना की साख का इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश हुई? आखिर वायुसेना ने तो इस तरह का कोई आधिकारिक बयान दिया नहीं था?

मजा या विडंबना यह है कि यह सवाल करते ही प्रधानमंत्री के अनुचर शोर मचाने लगे कि इस तरह के सवालों से पाकिस्तान को फायदा होता है. क्या सच जानने का अधिकार जनता का नहीं है? वायुसेना की कार्रवाई एक बड़ा कदम थी. पूरी दुनिया में इस पर चिंता जाहिर की गई.

भारत के इस कदम का समर्थन किसी ने नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी समय राजस्थान के चुरू में इस अत्यंत संकटपूर्ण क्षण में गर्दन मटकाते, मुस्कराते हुए यह कहकर सस्ती फिकरेबाजी की कि आज लोगों का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है. कुछ ऐसी ही बात तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी उन्होंने कही थी.

जिस समय भारत में लोग मिठाइयां खा रहे थे, उसका एक लड़ाकू पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में जा रहा था. भारत के लोगों को यह बात भी पाकिस्तान से मालूम हुई. लेकिन इस क्षण लगातार बोलनेवाले प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली.

इस पूरे दौर में जब भारत के प्रधानमंत्री भारत की जनता से नहीं, अपने दल के कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश को संबोधित कर रहा था. जब भारत के प्रधानमंत्री युद्धोन्माद उकसा रहे थे, तब इमरान खान अमन की अपील कर रहे थे.

जरूर उन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव होगा लेकिन यह तो इतिहास में दर्ज हो गया कि इस समय भारत के नेतृत्व ने शांति की भाषा का स्वागत नहीं किया. भारतीय पायलट को रिहा करने का कदम उठाकर इमरान खान ने एक बड़ी राजनयिक बढ़त हासिल कर ली है.

इसे भारत का मीडिया इस तरह पेश कर रहा है मानो पाकिस्तान भारत के पराक्रम से डर कर पीछे हट रहा है. राष्ट्रवादी नशे में भी हमें इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि यह 'समझौतावादी' कदम इमरान खान ने यह साबित करने के बाद उठाया कि अगर भारत के जहाज पाकिस्तान की सीमा पार कर सकते हैं तो पाकिस्तान भी उलट कर यह कर सकता है.

बल्कि भारतीय जहाज को मार गिराने और उसके एक लड़ाकू पायलट को पकड़कर अपनी सैन्य रणनीतिक कुशलता का प्रमाण भी उन्होंने अपनी जनता और दुनिया के सामने दे दिया. इसमें यह इशारा था कि अगर जंग छिड़ी तो वह एकतरफा न होगी और महंगी भी होगी, दोनों पक्षों के लिए.

इमरान खान के पहले राष्ट्रीय संदेश और फिर संसद में बयान की इस दरम्यान भारत के प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से तुलना स्वाभाविक है. और उसमें इमरान ऊंची सतह पर हैं.

उन्होंने भाषा की उदात्त शक्ति का प्रयोग किया जब यह कहा कि युद्ध का अंत तय करना शुरू करने वाले के बस में न होगा. इससे पाकिस्तान का आतंकवादी समूहों को पालने और उन्हें शह देने का पाप धुलता नहीं लेकिन इस बयान से एक संकटपूर्ण क्षण में संकीर्ण राष्ट्रवादी प्रलोभन का संवरण करने का संयम और साहस तो दिखता ही है.

यह अवसर हम सब के लिए होश बनाए रखने का और हर सरकारी कदम की सख्त पड़ताल का है. क्या हमारी सेना का इस्तेमाल एक राजनीतिक दल के हितों के लिए किया जा रहा है?

क्या हर मोर्चे पर विफल रहने के बाद राष्ट्रवाद का कवच कुंडल पहनकर, सेना को आगे रखकर शासक दल अगला चुनावी युद्ध लड़ेगा? और क्या हम ऐसा होते देखते रहेंगे क्योंकि हम पर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप लगने का खतरा है?